(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उद्योगों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने 30 अक्तूबर, 1998 को "1998-99 की मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा" सम्बन्धी एक विवरण जारी किया।

(ख) से (घ) ऊपर उल्लिखित नीति में वे उपाय शामिल होते हैं जो मूलतः दीर्घावधिक स्वरूप के होते हैं। इन उपायों का उद्देश्य सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप पूंजीगत प्रर्याप्तता के निर्धारण और अन्य विवेकपूर्ण मानदण्डों को सुदृढ़ बनाकर मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाना है। ये उपाय भविष्यगामी स्वरूप के हैं और एक निश्चित समयावधि में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाएंगे।

बैंकिंग प्रणाली में नकदी-निधि की स्थिति सन्तोषजनक है और औद्योगिक क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यताएं पर्याप्त रूप से वहन की जा सकती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक अर्थात् 6 नवम्बर, 1998 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए संसाधनों के कुल प्रवाह में 19,701 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 15,388 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में अधिक है। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए अल्पावधि उपायों अर्थात् बैंक दर, नकदी प्रारक्षित अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात और रिपो दर में किसी परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उपाय

1747. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए कुछ नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपायों के कारण मूल्य वृद्धि में कितने प्रतिशत गिरावट आयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए समुचित कदम कब तक उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

— प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ओ॰जी॰एल॰ के तहत इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

— नेफैड को आर्थिक सहायता प्रदत्त बिक्री के लिए प्याज की अधिप्राप्ति करने के लिए कहा गया।

— भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को अधिकृत किया गया है।

— ओ॰जी॰एल॰ के तहत दालों के आयात की अनुमति दी गई है और दालों के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

— सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 1.5 लाख टन खाद्य तेल की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है।

— वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा तेल का आयात करने पर 4 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

— मूल्य स्थिति पर निगाह रखने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति (सी॰ओ॰एस॰) की नियमित रूप से बैठक होती है।

मंत्रिमण्डल सचिव ने आश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। तदन्तर, 27.11.98 को हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक में अनेक कार्रवाई संबंधी मुद्दे तय किए गए, जिन पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) अधिकतर सब्जियों की कीमतों में दिसम्बर, में अद्योगामी प्रवृत्ति दिखाई देनी शुरू हो गई है और प्याज तथा आलूओं की कीमतों में पर्याप्त कमी आई है। इस कमी के आगे भी जारी रहने की सम्भावना है।

Transfer of IT Officials

1748. **SHRI JANARDAN YADAV:** Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Income Tax Officials have been transferred within three months affecting the ongoing investigation against a number of politicians; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Off-Loading of Shares by Foreign Financial Institutions

1749. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that a certain foreign financial institutions suddenly off-loaded shares worth about Rs. 100 crores and thus caused the sensex to fall as appeared in The Economic Times of 9th October, 1998;

(b) if so, whether Government are powerless in the matter; and

(c) what steps Government propose to take to prevent repetition of any such monkeying with Indian stocks?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) There are several factors, which influence the stock market. These include expectations of the investors regarding performance of the coporate sector and the economy in general, perceptions of the investors about the economic policies of the Government, developments in the international capital market, speculative activity etc. Therefore it is difficult to attribute a fall in sensex to trades by Foreign Institutional investors (FIIs) alone.

(b) and (c) The FIIs operate in the Indian Securities Market subject to guidelines/directives and regulations issued by the Government, RBI and SEBI.

Excise Duty Evastion by Small Scale Industries

1750. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a new system of control excise audit using professional financial accounting and auditing principles to replace the current system;

(b) if so, the details thereof indicating the changes proposed in the system alongwith its justification;

(c) what is the reaction of the industry and professional organisations to the proposed change in audit and account system; and

(d) details of preparatory steps taken for efficient and smooth change over to the new system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) The new Audit System envisages Selective Audit of the accounts of Central Excise assessess by adopting the principles of auditing instead of mere verification of accounts as at present. There will be an Audit Programme to identify precise areas of possible discrepancies/evasion. The concept of "Audit Protocol" is also being developed to have mutual cooperation between the Department and the assessees . The objective is to have an effective, transparent and assessee-friendly auditing. The new System has become essential consequent upon introduction of Self-Assessment System from October, 1996 and the on-going process of simplification of rules and procedures.

(c) The new Audit System is at a reparatory stage and the reaction of the industry will be obtained during the test audits.

(d) Several preparatory steps have been taken. The audit domcuments are being developed with expert advice of